



राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

Lokmanya Tilak: Planned A 'Hindu Asion?'

According to a few historical accounts, a plot was developed whereby Nepal's Hindu king would become a symbolic figure for Hindu unity.

Sit All Day? Here's How to Do Camel Pose

The Dire Need To Be Proactive in Modern Times

अयोध्या के नव निर्वाचित सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे लोकसभाध्यक्ष पद के लिए

सपा के अवधेश प्रसाद अयोध्या के नये सांसद हैं तथा दलित हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि अगर सरकार ने लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष से संपर्क कर सर्व सम्मति बनाने का प्रयास नहीं किया अथवा ऐसा प्रत्याशी नहीं चुना जो सभी को स्वीकार्य हो तो विपक्ष स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। स्पीकर का चुनाव लड़ने का दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देना चाहती है, जैसे कि पूर्व में परम्परा रही है। वर्ष 2014 में जब मोदी पहली बार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुए थे तब डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा की सहयोगी पार्टी अन्नाद्रमुक को दिया गया था और अन्नाद्रमुक के प्रत्याशी थम्बी दुरै को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। वर्ष 2019 में मोदी और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए थे तब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया था और ओम बिडुला ने भाजपा आदेश के अनुसार लोकसभा चलाई थी। विपक्ष ने तब चिन्ता नहीं कि स्पीकर के मुद्दे पर निर्णय 24 जून, जिस दिन

- विपक्ष को पूरा भरसा है कि, भाजपा सरकार विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करके "कॉमन" सर्वसम्मत स्पीकर पर सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं करेगी, क्योंकि, वो लोकसभा अध्यक्ष पद पर अपना ही विश्वासपात्र आदमी चाहेगी, यहाँ तक कि, संभवतया एन.डी.ए. के अन्य घटकों को भी विश्वास में नहीं लेगी।
- विपक्ष अपना उम्मीदवार इसलिये भी खड़ा करना चाहती है, क्योंकि, उसका यह भी मानना है कि, भाजपा, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी विपक्ष को ऑफर नहीं करेगी, वैसे संसदीय परम्परा के अनुसार, उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष का नुमाइंदा बैठता आया है।
- विपक्ष स्पीकर के पद के लिये चुनाव लड़कर, यह भी भांपना चाहती है कि, अन्ततोगत्वा इंडिया गठबंधन (विपक्ष) के समर्थन में कितने सांसद हैं। क्योंकि, कई छोटे-छोटे राजनीतिक दल, जैसे जगन रेड्डी की पार्टी, अन्नाद्रमुक, अकाली दल व बी.जे.डी. ने अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि, वे किस ग्रुप में हैं, सरकारी पक्ष या विपक्ष।
- और अगर स्पीकर के पद का चुनाव हुआ तो इन दलों को अपना सोच सार्वजनिक करना ही पड़ेगा।
- स्पीकर के पद का चुनाव 26 जून को है, अतः सभी राजनीतिक दलों को 24 जून तक इस बारे में निर्णय लेना ही पड़ेगा।

संसद सत्र शुरू होगा, से पहले ही हो जाना चाहिए। स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा है। विपक्ष को यह उम्मीद नहीं है कि स्पीकर का पद भाजपा किसी सहयोगी

दल को देगी, क्योंकि भाजपा लोकसभा पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है। विपक्ष को यह भी उम्मीद नहीं है कि भाजपा किसी एक नाम पर सर्व सम्मति के लिए विपक्ष के साथ कोई

विचार-विमर्श करेगी। यह मोदी की कार्यशैली नहीं है। बहुत कम लोगों को लगता है कि मोदी की कार्यशैली में कोई बदलाव होगा। विपक्ष ने तय किया है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी वाराणसी से किसानों को 20,000 करोड़ बांटेंगे

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वाराणसी जा रहे हैं, वे वहाँ पी.एम. किसान स्कीम के तहत किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रूपये की 17वीं किश्त वितरित करेंगे। वे वहाँ स्वयं सहायता समूह की

- प्रधानमंत्री किसान योजना की 17वीं किश्त बांटने के लिए मंगलवार को वे वाराणसी जाएंगे। इस दौरान 30,000 स्वयं सेवी समूहों को "कृषि सखी" प्रमाण पत्र देगे।

30,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देगे। दिल्ली में आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का कार्यभार संभालते ही सर्वप्रथम "किसान सम्मान निधि" की फाईल पर हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 9.26 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को पी.एम. वाराणसी से एक बटन दबाकर यह राशि वितरित करेंगे। चौहान ने कहा कि किसान सम्मान

'न मैं स्पीकर शिप पर अडूँ, न विभागों के वितरण पर रोष दिखाऊँ'

"पर, आप बिहार में मध्यावधि चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखण्ड के साथ करा दें": नीतीश कुमार ने मोदी से गुहार की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। लोकसभा स्पीकर के पद के लिए भाजपा प्रत्याशी को बिना शर्त समर्थन देने की एवज में जद (यू) प्रमुख नीतीश कुमार का अपग्रह है कि भाजपा बिहार के विधानसभा चुनाव समय से पूर्व इसी वर्ष महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ ही करवा दिए जाए।

नीतीश कुमार शीघ्र चुनाव चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में एन.डी.ए. के अच्छे प्रदर्शन के बाद राज्य में जद (यू) के पुनर्निर्माण के बेहतर अवसर है। राज्य को 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर एन.डी.ए. जीता है। जद (यू) व भाजपा को 12-12 सीटें मिली है तथा 5 सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को और एक जितनराम की हिन्दुस्तान अवािम मोर्चा को मिली है। पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी बिहार महागठबंधन के दल बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। यहां राजद ने 4, कांग्रेस तीनों दो सीटें वामपंथी दलों ने और एक निर्दलीय पप्पू यादव ने जीती है। जद (यू) विधायक दल की हालिया मीटिंग में यह बात रखी गई है

- नीतीश की जिन के पीछे कारण हैं कि, वे मानते हैं कि, अभी वर्तमान माहौल में अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी, जद (यू) के लिये इससे बेहतर समय नहीं आयेगा।
- मोदी अभी जद (यू) पर निर्भर हैं। अतः सीटों के बंटवारे आदि, अन्य चुनावी मुद्दों पर मोदी को मनाया जा सकता है, और अगर अगले वर्ष समय से ही चुनाव होते हैं, तो क्या पता मोदी छोटे-छोटे दलों का साथ लेकर जद (यू) पर इतने निर्भर नहीं रहेंगे, तथा चुनाव उतना ही मुश्किल हो जायेगा।
- पर, बिहार के भाजपा नेता जल्दी, समय से पूर्व, चुनाव कराने के विरोध में हैं। इन नेताओं के अनुसार, अगर एन.डी.ए. मध्यावधि चुनाव जीत भी गया तो भाजपा को पुनः नीतीश के छाते के नीचे ही खड़ा होना पड़ेगा, अगले पाँच साल तक, तथा शुद्ध भाजपा की सरकार बनाने के लिये और पाँच साल इंतजार करना पड़ेगा।

जि इस समय जबकि नेत्रेन्द्र मोदी की सरकार पूरी तरह से जद (यू) पर निर्भर है तब सीटों के बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे पर भाजपा से बेहतर डील कर सकती है। मान लीजिए अगर बिहार के चुनाव अगले वर्ष नवम्बर में निर्धारित समय पर होते हैं तो संभावना है कि तब तक भाजपा लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ा लेगी और हो सकता है उसकी जद (यू) पर निर्भरता खत्म हो जाए। कुमार समझते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ समय है। दूसरी ओर भाजपा नेता जल्दी चुनाव के खिलाफ हैं। पार्टी नेता कहते हैं कि अगर शीघ्र चुनाव करवाने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारी जीत की शुरुआत है, अंत नहीं'

उद्धव ठाकरे, शरद पवार व पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) की जीत तो एक शुरुआत है अंत नहीं। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष का गठबंधन ही जीतेगा। ठाकरे ने एक संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। कॉन्फ्रेंस में एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण भी बोले। तीनों दलों ने राज्य के वर्धन में होने वाले चुनावों को लेकर प्रार्थमिक वार्ता की। ठाकरे ने कहा कि "राज्य की जनता ने दिखा दिया है कि भाजपा अजेय है यह मिश्रक कितना खोखला है। लोकसभा चुनाव की जीत महाविकास अघाड़ी के लिये अंत नहीं शुरुआत है।" इसी बीच शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। लोकसभा

- जैसा कि विदित ही है, संसदीय चुनावों में महविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से तीस पर विजय हासिल की है।
- कांग्रेस, जिसे पिछले चुनाव में एक सीट पर विजय मिली थी, ने इस बार तेरह सीटें जीतीं, शिव सेना (उद्धव ठाकरे ग्रुप) ने नौ सीटों पर जीत हासिल की, तथा शरद पवार की एन.सी.पी. ने आठ सीटें जीतीं।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि, उद्धव ठाकरे की शिव सेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 17 पर व एन.सी.पी. (पवार ग्रुप) ने 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किये थे।

चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 महाविकास अघाड़ी ने जीती। पवार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राज्या में एम.वी.ए. के पक्ष में माहौल बनाया। महाराष्ट्र ने भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर सार्वजनिक एवं निजी स्तर पर कई कटाक्ष किए जा रहे हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने यहां से 23 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा 9 सीटें ही जीत पाई। मोदी ने जिन 18 सीटों पर जोरदार प्रचार

किया था, भाजपा उनमें से 15 सीटों पर हार गई। इनमें तीन सीटें मुम्बई की थीं, मुम्बई नॉर्थ (केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल), नॉर्थ वेस्ट मुम्बई (रविन्द्र वाइकर-शिवसेना शिंदे ग्रुप), सतारा (भाजपा के उदयनराज भोंसले)। कांग्रेस नेता चौहान ने कहा कि लोक सभा चुनावों के परिणामों के बाद महाराष्ट्र सरकार का बदलाव अश्यंभावी है। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा पवार ने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लंग कैंसर सूंघ लेती हैं मधुमक्खियाँ

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। एक नए शोध के अनुसार मधुमक्खियाँ इंसान की सांस में मौजूद फेफड़ों के कैंसर से सम्बंधित बायोमार्कर्स और रसायनों को पहचान कर सकती हैं। शोध के नतीजों के अनुसार

- मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के अस्सिस्टेंट प्रोफेसर देबजीत साहा ने एक शोध में यह बताया। उन्होंने कहा कि, कुत्ते की तरह मधुमक्खी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है।

मधुमक्खी सैल कल्चर्स को सूंघ कर अलग-अलग प्रकार की लंग कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकती हैं। इन नतीजों का इस्तेमाल फेफड़ों के कैंसर की समय से पूर्व पहचान करने के लिए बतौर मॉडल किया जा सकता है। मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटिटेटिव हेल्थ साइंस एण्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये कमीशन गठित होने से पूर्व मु.मंत्री के.सी.आर. तिलमिलाये

के.सी.आर. ने इन्क्वायरी कमीशन के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी को पत्र लिखकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की राय दी

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस्.) सुप्रिमो के चन्द्रशेखर राव (के.सी.आर.) ने अपने शासनकाल के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर की जा रही जाँच के लिए एक जूडीशियल कमीशन गठित करने से तिलमिला गए हैं। उन्होंने इस कमीशन को अवैध बताया है। के.सी.आर. ने जस्टिस एल. नरसिंह रेड्डी को 12 पृष्ठों का एक कठोर पत्र लिखकर उन पर आरोप लगाया है कि उनका आचरण हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज जैसा नहीं है। पत्र में जस्टिस नरसिंह रेड्डी से माँग की गई है कि वे जाँच कमीशन से स्वयं का हटा लें। जस्टिस रेड्डी कमीशन के.सी.आर. के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए गए विभिन्न पावर पंचेज एग्जीमैन्ट्स (पी.पी.ए.) की जाँच कर रहा है। के.सी.आर. ने एग्जीमैन्ट्स में हुई किसी भी अनियतता का पुरजोर खण्डन करते हुए कहा है कि

- पूर्व मु.मंत्री चन्द्रशेखर राव (के.सी.आर.) ने अपने शासनकाल में बाहर से बिजली खरीदने के कई अनुबंधन किये थे। पर, अब यह आरोप लग रहा है कि, इन अनुबंधनों पर हस्ताक्षर करने के पहले पावर सफाई करने वाली कंपनियों से अरबों रूपए का लैन-देन हुआ था।
- के.सी.आर. अपने पक्ष में यह कह रहे हैं कि, सभी एग्जीमैन्ट्स राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार से स्वीकृति लेकर ही किए गए हैं तथा, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलैटरी कमीशन के सभी आदेशों की भी राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से अनुपालना की है।

उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार से जरूरी अनुमति प्राप्त की थी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर उल्टे बदनाम करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए के.सी.आर. ने कहा कि "यह मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने इन्क्वायरी कमीशन की परम्पराओं के विपरीत जाँच समाप्त होने से पूर्व ही एक प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। कानूनी कार्रवाई एक पवित्र कर्तव्य होता है क्योंकि जब दो पक्षों में कोई विवाद

उत्पन्न होता है तब न्यायिक मध्यस्थ ही सच को सामने लाता है। तथ्यों और पहलुओं के विस्तृत परीक्षण के बाद ही दस्तावेजो साक्ष्य के जिनमेवारा लोगों को रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ 1000 मेगावाट के सावर परचेज एग्जीमैन्ट तथा 4 X 270 मेगावाट के मदद्री थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस्.) और

8 X 800 मेगावाट के यदद्री थर्मल पावर स्टेशन (वाय.टी.पी.एस्.) के कार्य सम्पादन में हुई कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए इस वर्ष के मार्च माह में जस्टिस रेड्डी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। के.सी.आर. ने कमीशन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने जाँच के परिणाम को पहले से ही तय कर लिया है। उन्होंने लिखा कि "ऐसा लगता है कि आपकी जाँच में कोई निष्पक्षता नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आपके समक्ष में जो भी कुछ कहता हूँ, उसका कोई तुक नहीं है। उक्त सभी पर विचार करते हुए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप इस जाँच कमीशन से स्वेच्छा से हट जाएं।" के.सी.आर. ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए कमीशन की जाँच की वैधता पर सवाल खड़े करते हुए उसे गैर कानूनी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि पी.पी.ए. के लिए इलैक्ट्रिसिटी एक्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में पेट्रोल-डीज़ल 3 रूपए प्रति लीटर महंगा

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल व डीज़ल के दामों में भारी वृद्धि करने की भाजपा ने तीव्र

- पेट्रोल व डीज़ल के दाम बढ़ाने के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करने वाली कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसकी भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भर्त्सना की है, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्रीकर में वृद्धि की है। प्रदेश सरकार जिसने एक वर्ष तक ईंधन पर टैक्स नहीं बढ़ाया था पर अब बढ़ा दिया, इसका परिणाम यह होगा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू.पी. में दस एम.एल.ए. सीटों पर "बाय-इलैक्शन" होंगे शीघ्र ही

भाजपा व सपा के नौ विधायक सांसद निर्वाचित हुए हैं अतः उन्हें अपनी एम.एल.ए. सीटों से इस्तीफा देना होगा, कुछ नये सांसद तो दे भी चुके हैं, और कुछ इस्तीफा देने की तैयारी में हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 15 जून। हाल ही सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावों में लगे तगड़े झटके के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में इण्डिया गठबंधन की कड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के 9 विधायक विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी रहे थे। लोकसभा सीटें जीतने के बाद इनमें से कुछ तो अपनी विधानसभा सीटों से पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में देंगे। सिसामऊ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हरफान सोलंकी को आगजनी के एक केस में

- दसवीं सीट, जिस पर बाय-इलैक्शन होना है, वह है, सीसामऊ की सीट, जहाँ से सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। पर, इरफान सोलंकी को एक आगजनी के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है तथा उन्हें सात वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई है। अतः इरफान सोलंकी को भी अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ भी "बाय-इलैक्शन" होना अनिवार्य है।
- 2022 तक विधानसभा सीटों पर चुनाव मुख्यतया सपा व भाजपा के बीच ही हुए थे। पर, इस बार इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण सदस्य होने के कारण कांग्रेस बाय-इलैक्शन में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है।
- बाय-इलैक्शन में तीव्र संघर्ष होने की संभावना है। संसदीय चुनावों में, यू.पी. में भारी हार के बाद, भाजपा पूरा जोर लगायेगी, यह साबित करने के लिये कि, संसदीय चुनाव में हार का मतलब यह नहीं है कि, यू.पी. में उसका जनाधार खत्म हो गया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, सपा व कांग्रेस संसदीय चुनाव में भारी जीत से बने माहौल व कार्यकर्ताओं के मनोबल को बरकरार रखने के लिये, उपचुनाव में जीत को भारी महत्व दे रहे हैं।

को शुरू में कन्नौज लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 तक विधानसभा उप चुनावों में मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जाता था, किन्तु अब कांग्रेस भी इण्डिया गठबंधन के भागीदार के रूप में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रही है। वर्ष 2022 के

विधानसभा चुनाव में करहल सीट से अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी एवं सपा के पूर्व नेता एस.पी. सिंह बघेल को 67 हजार वोटों के बड़े अन्तर से हरा दिया था। बघेल अब भाजपा टिकट पर आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पुनः जीते हैं और उन्हें भाजपा नेतृत्व वाली नई एन.डी.ए. सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से भाजपा के बाबा गोरखनाथ को करीब 13 हजार वोटों से हराया था। प्रसाद "पासी" (दलित) समुदाय से हैं और अयोध्या से सांसद चुने गए हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से पासी जाति के प्रत्याशी से हारने के बाद भाजपा अब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किसी पासी प्रत्याशी को उतारने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- बताया जाता है कि झाइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ और ट्रैवलर बस 500 फीट नीचे नदी में गिर गई, हादसे में 14 अन्य घायल भी हुए हैं। इनमे 7 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। जबकि, 7 घायलों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मय फोर्स मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू में जुट गए। हादसे की वजह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

